मदन राठौड़ भारतीय जनता पार्टी के निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष घोषित

मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा, भाजपा विचारधारा आधारित पार्टी है, हर कार्यकर्ता विचारधारा का निर्वहन करता है

राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ फिर से निर्विरोध राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पार्टी का दुप्पटा पहनाकर उनका स्वागत किया।

- निर्वाचन के बाद मदन राठौड़ ने कहा, भाजपा में एक पद के लिये कई योग्य उम्मीदवार हैं और यह भी हमारी पूँजी व धरोहर है।
- केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि भाजपा लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्वहन करने वाली विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है।

जयपुर, 22 फरवरी । भाजपा संगठन पर्व 2024 के तहत, शनिवार को प्रदेशाध्यक्ष एवं राष्ट्रीय परिषद सदस्य निर्वाचन बैठक में राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष चुनाव अधिकारी विजय भाई रूपाणी ने मदन राठौड़ को निर्विरोध भाजपा प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया। शुक्रवार को एक मात्र नामांकन दाखिल होने के बाद नामांकन पत्रों की जांच और पार्टी संविधान तथा चुनावी नियमों के चलते, आधिकारिक रूप से शनिवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद पर मदन राठौड़ का नाम घोषित किया गया।

राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष चुनाव अधिकारी विजय भाई रूपाणी ने प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की घोषणा के साथ ही, 25 सदस्य राष्ट्रीय परिषद के भी घोषित किए। ये सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया में शामिल होंगे। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, डिप्टी सीएम दीया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अरुण चतुर्वेदी, अशोक परनामी, डॉ. सतीश पूनिया, सीपी जोशी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़, भाजपा नेता ओंकार सिंह लखावत, नारायण पंचारिया, सीआर चौधरी, अलका गुर्जर, अनीता भदेल, अजय पाल सिंह, निर्मल कुमावत, प्रसनजीत मेहता, मदन दिलावर, जोगाराम पटेल, अनीता गुर्जर, प्रभु लाल सैनी, रमेश यादव, जसवंत सिंह गुर्जर, रामकिशोर मीणा, प्रताप लाल और ओमप्रकाश के नाम शामिल हैं।

बैठक को संबोधित करते हुए चुनाव अधिकारी विजय रूपाणी ने कहा कि जनसंघ से लेकर जनता पार्टी और फिर भाजपा में अनेकों कार्यकर्ताओं और नेताओं ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तब जाकर आज सशक्त भाजपा देश भर में मजबूती से उभर कर सामने आई है। रूपाणी ने भाजपा की कार्यशैली पर चर्चा करते हुए बताया कि भाजपा में 5 "के" पर कार्य किया जाता है, इनमें कार्यकर्ता, कार्यक्रम, कार्यालय, कोष और कार्य पद्धति शामिल है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि संगठन और सरकार एक दूसरे के पूरक है। संगठन और सरकार जब कार्य करते हैं तो जनसेवा होती है। हमारे कार्यकर्ताओं ने अपनी कई पुरानी पीढ़ियां जनसंघ, जनता पार्टी और भाजपा के लिए खपा दीं। भाजपा विचारधारा वाली पार्टी है, इसका प्रत्येक कार्यकर्ता विचारधारा को साथ में लेकर अपने दायित्वों को पूरा करने में जुटा हुआ है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान के कार्यकर्ताओं की टोली पर हमें विश्वास है। इन कार्यकर्ताओं की बदौलत हम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकास के विजन को पूरा करेंगे।

भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मदन राठौड़ की प्रशंसा करते हुए कहा कि राठौड़ कर्मठ, समर्पित, संस्कारित, सेवाभावी और ईमानदार कार्यकर्ता हैं। इन सबके चलते ही देश के सबसे बड़े प्रदेश की जिम्मेदारी आप को मिली है। हम सभी को उम्मीद के साथ पूर्ण विश्वास है कि मदन राठौड़ सबको साथ लेकर चलेंगे।

भाजपा प्रदेश प्रभारी डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि मदन राठौड़ ने 7 माह में अपनी मेहनत से, समर्पण भाव से, निष्ठा से, व्यवहार कुशलता से और जनता व कार्यकर्ताओं के साथ चरैवेति-चरैवेति के सिद्धांत पर कार्य किया।

भाजपा के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि मैं आज के इस निर्वाचन कार्यक्रम में अपने सहयोगियों के उद्बोधन को पाथेय के रूप में सहेज कर रखूंगा। हमारी पार्टी में पद के लिए कई योग्य उम्मीदवार हैं, यह ही हमारी पूंजी है, यह ही हमारी धरोवर है। दायित्व तो एक को ही मिलेगा, लेकिन योग्य बहुत हैं। एक- एक कार्यकर्ता को तैयार करने के लिए संगठन बहुत कुछ दाव पर लगाता है। दायित्व जिसको मिलेगा, उसे अपना कत्तर्व्य मानकर पूरा करेगा।

केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्वहन करने वाली विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, एक विचारधारा पर कार्य किया जाता है।

बैठक में संगठन पर्व प्रदेश संयोजक नारायण पंचारिया ने संगठन पर्व को लेकर प्रस्तावना रखी, वहीं संगठन पर्व चुनाव सह संयोजक सुशील कटारा ने मंच संचालन किया।

इस मौके पर डिप्टी सीएम दीया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, संगठन पर्व अपील अधिकारी घनश्याम तिवाड़ी, सक्रिय सदस्यता अभियान के प्रदेश संयोजक ओंकार सिंह लखावत मंच पर उपस्थित रहे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री, विधायक और पार्टी पदाधिकारी तथा अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे।

बैठक के बाद, भाजपा के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रदेश प्रभारी डॉ राधा मोहन दास अग्रवाल, प्रदेश संगठन चुनाव अधिकारी नारायण पंचारिया के साथ मिलकर सभी जिलाध्यक्षों के साथ बैठक की।

उलझता जा रहा है शशि थरुर का मसला कांग्रेस में

तिरुवनंतपुरम, 22 फरवरी। कांग्रेस में सब ठीक नहीं है। एक के बाद एक बड़े नेता पार्टी से दूर होते जा रहे हैं। अब मामला शशि थरूर का है। शशि थरूर ने राहुल गांधी से अपनी भूमिका के बारे में सवाल किया है। दरअसल शशि थरूर ने पीएम मोदी की तारीफ की। इसके बाद कांग्रेस ने शशि थरूर के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया। उनके खिलाफ कांग्रेस के मुखपत्र में लेख भी छपा। इसके बाद अब शशि थरूर कांग्रेस पर बरस पड़े।

- राहुल गांधी ने थरुर से बात तो की पर उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर के साथ नरमी बरतने के मूड में नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने थरूर से बातचीत तो की, लेकिन उनकी शिकायतों और सुझावों पर कोई ध्यान नहीं दिया। शशि थरूर ने राहुल गांधी से पार्टी में अपनी भूमिका स्पष्ट करने को कहा था। कुछ दिन पहले दिल्ली में हुई बातचीत में थरूर ने पार्टी में किनारे किए जाने पर गहरी नाराजगी जताई। सुना है कि राहुल गांधी कोई ठोस वादा करने को तैयार नहीं थे, इसलिए थरूर इस बातचीत से नाखुश हैं।

महाशिवरात्रि पर कुंभ में भीड़ के लिये विशेष व्यवस्था होगी

प्रयागराज में प्रशासनिक स्तर पर सारे प्रयास किये जा रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को असुविधा न हो

महाकुंभनगर, 22 फरवरी। महाकुंभ का भव्य आयोजन अब अपने आखिरी पड़ावद्ध 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के आखिरी स्नान पर्व की ओर अग्रसर है, जिसके लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी रवीन्द्र मांदड़ ने शनिवार को बताया कि महाकुंभ में 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालु देश-दुनिया से आकर डुबकी लगाएंगे, ऐसे में उनकी यह यात्रा सुखद रहे इस बात को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर तमाम तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। आखिरी स्नान पर्व को देखते हुए इन प्रयासों में तेजी लाई गई है।

- राज्य सरकार के निर्देश पर सभी अधिकारी - कर्मचारी ऑन फील्ड रहकर तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं।

रवीन्द्र मांदड़ के अनुसार, अधिकारी-कर्मचारी ऑन फील्ड रहकर मॉनिटर कर रहे हैं। वीकएंड्स, पीक डे व अवकाश के दिनों में ट्रैफिक डायवर्जन की स्कीम को पुलिस लगाती है। इसके लिए पुलिस के अधिकारियों को भी ब्रीफ करके सचेत किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। शहर के सभी बॉर्डर्स पर जिलों के साथ अच्छा समन्वय व तालमेल स्थापित किया जा रहा है।

मांदड ने बताया कि कहीं पर भी डायवर्जन लागू करने के लिए डीएम, एसपी से भी लगातार संवाद बना हुआ है।

'नीतीश कुमार के पुत्र राजनीति में आते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं'

भागलपुर,22 फरवरी (वार्ता) बिहार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अध्यक्ष एवं भूमि सुधार और राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत राजनीति में आएं या नहीं आएं,यह उनकी इच्छा है, इसमें भाजपा को कोई एतराज़ नहीं है।

जायसवान ने शनिवार को यहां संवाददाताओं से बातचीत करते हुए

- बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि नीतीश पर परिवार वाद का आरोप कदापि नहीं लगेगा।

कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चालीस साल से बिहार और देश में सक्रिय राजनीति में हैं, यदि वे चाहते तो इस दौरान अपने पुत्र को राजनीति में अवश्य लाते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे पूर्ण रुप से एक समाजवादी नेता रहे हैं। उनके पुत्र यदि अब राजनीति में आते हैं तो उनके पिता नीतीश कुमार पर परिवारवाद का आरोप कदापि नहीं लगेगा।

'महंगी और दोषपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का परिणाम है पेपर लीक'

बिहार के बहुचर्चित खान सर ने कहा कि लोग महंगी पढ़ाई पर खर्च करने के बजाय प्रश्न पत्र खरीदने में लाभ देखते हैं

मुंबई, 22 फरवरी। बिहार में कोचिंग सेंटर चलाने वाले चर्चित खान सर ने शनिवार को यहां कहा कि भारत में पेपर लीक की समस्या महंगी और दोषपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का परिणाम है और इसलिए लोग महंगी पढ़ ाई पर खर्च करने के बजाय प्रश्न-पत्र खरीदने में लाभ देखते हैं । वे एक टीवी समाचार चैनल द्वारा आयोजित एक चर्चा सत्र में भाग ले रहे थे।

ग्लोबल स्टडीज़ एण्ड खान जीएस रिसर्च सेंटर के संस्थापक खान सर ने जीवन-यापन के लिए पढ़ ायी-लिखाई के महत्व पर एक सत्र में पेपर लीक के मुद्दे पर भी विचार रखे। इस सत्र का विषय था-'द टवैंटी फर्स्ट सेंचुरी इंडियन- लर्निंग टू सरवाइव।'

- मैडिकल शिक्षा पर खान सर ने कहा कि सरकारी कॉलेज में कम शुल्क पर शिक्षा सुलभ हो जाती है जबकि निजी संस्थानों की फीस बहुत ज्यादा है। अतः छात्र चाहते हैं कि लाखों की फीस देने के बजाय उन्हें लीक हुआ पेपर मिल जाये।

उन्होंने शिक्षा प्रणाली की खामियों पर बात करते हुए मेडिकल कॉलेज की फीस में भारी अंतर की ओर इशारा करते हुए कहा, "सरकारी कॉलेज बहुत कम शुल्क लेते हैं जिससे शिक्षा सुलभ हो जाती है। लेकिन वहीं निजी संस्थानों की फीस बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए छात्र चाहते हैं कि उन्हें लाखों रुपए की फीस देने के बजाए लीक हुआ पेपर ही मिल जाए। भारत में शिक्षा इतनी महंगी है कि छात्र विदेशों की ओर रुख कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, अकेला व्यक्ति 140 करोड़ लोगों के देश को नहीं बदल सकता, हमें अपने भीतर से बदलाव शुरू करना होगा। हमें तय करना होगा कि छात्र सिर्फ परीक्षा के लिए ही नहीं बल्कि अपने जीवन के लिए भी तैयार हों।'

उन्होंने कहा, हर छात्र को मजबूत भविष्य बनाने के लिए कोई स्किल सीखना चाहिए, फिर चाहे वह किसी भी कोर्स से जुड़ा हो। शिक्षा, एकेडमी से दायरे से बढ़ कर होनी चाहिए, छात्रों को रोज़गार क्षमता पर ध्यान देना चाहिए।

उन्होंने कहा, हमें हर साल नए कौशल सीखने चाहिए, फिर चाहे वह ड्राइविंग हो या कोई और चीज़। सही कौशल पाने से आपकी रोज़गार क्षमता बढ़ ती है।'

उन्होंने ऐडटेक कंपनियों की खामियों पर बात करते हुए कहा , इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर फीचर्स तो होते हैं, लेकिन शिक्षा के लिए फीचर्स के साथ-साथ अध्यापकों का होना भी ज़रूरी है।

'अगर तमिलनाडु ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

समय से अब तक कांग्रेस, तमिलनाडु की सत्ता से बाहर ही रही तथा वह निकट या दूरगामी भविष्य में इस राज्य की सत्ता में आने की आशा भी नहीं कर सकती। भाजपा, जो तमिलनाडु की राजनीति में फर्क लाने की उम्मीद करती है और भाषा के मुद्दे पर अपनी आक्रामक नीति जारी रखती है तो उसे राज्य में अपनी संभावनाओं की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। 1960 के दशक से, तमिलनाडु के लोगों ने कभी भी राष्ट्रीय पार्टियों को अपनी सरकार चलाने का मौका नहीं दिया।

रेत में दबने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

भाग गया। अधिकारी ने बताया कि मलबे से एक लड़की और एक महिला को बचा लिया गया है। उन्होंने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और चालक का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। मृतकों की पहचान सिल्लोड तहसील के गोलेगांव निवासी गणेश धनवाई (60) और उनके बेटे भूषण धनवाई (16) तथा जाफराबाद तहसील के पद्मावती निवासी सुनील सपकाल (20) के रूप में हुई है। उन्होंने कहा कि अन्य दो पीड़ितों की पहचान अभी नहीं हो पाई है।

शक्तिकांत दास ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

में मुख्य रूप से फाइनेंस, टेक्सेशन, इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में काम किया है। वे भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर बने और उन्होंने भारत के जी20 शेरपा तथा 15वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में भी काम किया है। बता दें कि शक्तिकांत दास पीएम मोदी के बेहद भरोसेमंद माने जाते हैं। शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें गवर्नर रह चुके हैं। दास ने 11 दिसंबर 2018 को उर्जित पटेल के बाद आरबीआई गवर्नर का पदभार संभाला था। पटेल के अचानक इस्तीफे के बाद दास की नियुक्ति हुई थी। शक्तिकांत दास आईएमएफ, जी 20 और ब्रिक्स जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। नोटबंदी और जीएसटी, जैसे बड़े सुधारों में दास ने अहम भूमिका निभाई थी। रिजर्व बैंक के गवर्नर रहते उन्होंने वित्तीय स्थिरता और आर्थिक विकास पर फोकस किया। कोरोना महामारी के दौरान उनकी नेतृत्व क्षमता ने भारतीय अर्थव्यवस्था को काफी सहारा दिया।

आज से मोदी एम.पी, बिहार व असम का दौरा करेंगे

नई दिल्ली, 22 फरवरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि 23 फरवरी से राज्यों के मैराथन दौरे पर रवाना हो रहे हैं। प्रधानमंत्री का दौरा 25 फरवरी को समाप्त होगा। प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश, बिहार और असम जाएंगे। जहां वे विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, साथ ही कई योजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएमओ से मिली जानकारी के अनुसार प्र.मंत्री मोदी सबसे पहले 23 फरवरी को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की यात्रा करेंगे, जहां वह दोपहर करीब 2 बजे बागेश्वर धाम चिकित्सा एवं विज्ञान अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखेंगे।

इस संस्थान का उद्देश्य कैंसर सहित गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना है। संस्थान में अत्याधुनिक तकनीक और विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाएं मिलेंगी, जिससे जरूरतमंद मरीजों को मुफ्त उपचार मिल सकेगा।

- इस यात्रा में प्रधानमंत्री कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे।

छतरपुर के बाद 24 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी सुबह करीब 10 बजे भोपाल पहुंचेंगे। जहां वे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2025 का उद्घाटन करेंगे। यह सम्मेलन मध्य प्रदेश को वैश्विक निवेश केन्द्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। इसमें 60 से अधिक देशों के प्रतिनिधि, विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों के अधिकारी और भारत के 300 से अधिक प्रमुख बिजनेस लीडर्स हिस्सा लेंगे।

इसी दिन प्रधानमंत्री मोदी बिहार के भागलपुर जाएंगे, जहां दोपहर करीब सवा दो बजे वे प्रधानमंत्री किसान योजना की 19वीं किस्त जारी करेंगे। इस योजना के तहत देशभर के 9.7 करोड़ से अधिक किसानों को 21,500 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने और उन्हें संगठित करने के लिए 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन के लक्ष्य को पूरा करने की घोषणा भी करेंगे। इसके अलावा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत निर्मित स्वदेशी नस्लों के लिए उत्कृष्टता केन्द्र का उद्घाटन करेंगे, जिसका उद्देश्य आधुनिक प्रजनन तकनीकों को बढ़ ावा देना और स्वदेशी नस्लों के संरक्षण को सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही, बरौनी में एक दुग्ध उत्पाद संयंत्र का उद्घाटन किया जाएगा, जिससे 3 लाख से अधिक दुग्ध उत्पादकों को संगठित बाजार उपलब्ध होगा।

प्रधानमंत्री मोदी बिहार में बुनियादी ढ ांचे और कनेक्टिविटी को बढ़ ावा देने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे।

अब 19 मार्च को होगी किसान संगठनों के साथ केन्द्र सरकार की वार्ता

चंडीगढ़ , 22 फरवरी। फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) समेत अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों के प्रतिनिधिमंडल और केन्द्र सरकार के बीच शनिवार (22 फरवरी) को चंडीगढ़ में छठे दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। ढ ाई घंटे चली मीटिंग में कोई हल नहीं निकला। अब अगली मीटिंग 19 मार्च को चंडीगढ़ में ही होगी। मीटिंग के बाद केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा- बैठक अच्छे माहौल में हुई। हमने मोदी सरकार की प्राथमिकताएं किसानों के सामने रखीं।

कांग्रेस विधायकों ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

का सदन में दूसरे दिन शनिवार को भी धरना जारी रहा। वार्ता विफल होने के बाद, अब सोमवार तक धरना जारी रहने की संभावना है। शनिवार और रविवार को विधानसभा की छुट्टी है। सोमवार को ही अब सदन चलेगा। ऐसे में धरना तब तक खिंचने के आसार बन गए हैं।

ट्रम्प का अमेरिका के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अमेरिका की वर्तमान दिशा की तुलना द्वितीय विश्व युद्ध से पहले के ब्रिटेन से करते हुए फर्ग्यूसन ने आशंका जताई कि आर्थिक प्रतिबंध 'डिफॉल्ट, मूल्यह्रास, और साम्राज्य के पतन' का कारण बन सकते हैं। वे जोर देते हैं कि केवल कट्टर सामाजिक कल्याण सुधार–जिन्हें लगातार प्रशासनों द्वारा नजरअंदाज़ किया गया है–वित्तीय पतन को रोक सकते हैं। इसके बिना, अमेरिका की उम्मीद एक अभूतपूर्व "उत्पादकता चमत्कार" ही हो सकती है। इस बीच, ट्रंप उच्च-स्तरीय कूटनीति में उलझे हुए हैं। जिस दिन फर्ग्यूसन की चेतावनी सुर्खियों में आईं, उसी दिन खबर आई कि ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेन्स्की पर रूस के साथ शांति के लिए खनिज संपत्तियों के समर्पण करने का दबाव डाला। इस डील, जिसे तीन साल के संघर्ष को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा था, ने कूटनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। कुछ दिन पहले, ज़ेलेन्स्की ने घोषणा की थी, "मैं यूक्रेन की रक्षा करता हूँ, मैं हमारे देश को नहीं बेच सकता।" लेकिन शुक्रवार को उन्होंने स्वीकार किया कि यूक्रेन और अमेरिका के अधिकारी कीव के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक आर्थिक समझौते पर हस्ताक्षर कर रहे थे। ट्रम्प ने कहा, "हम एक समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं, उम्मीद है कि जल्दी ही समझौता हो जाएगा"। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बाद में पुष्टि की कि समझौता होने ही वाला है। बातचीत तनावपूर्ण थी। एक्सियोस ने रिपोर्ट किया कि ट्रंप, ज़ेलेन्स्की के प्रतिरोध से परेशान होकर, अमेरिकी सहायता को रोकने की धमकी दे रहे थे। सूत्रों का कहना है कि यूक्रेन नेता ने अमेरिकी वार्ता टीम, जिसमें ट्रंप, जे.डी. वेंस, मार्को रुबियो, ट्रेज़री सचिव स्कॉट बासेंट और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल वॉल्ट्स शामिल थे, की धैर्य की सीमा समाप्त कर दी पर अन्ततः यूक्रेन के राष्ट्रपति समझौते के लिए सहमत हो गए।

ट्रंप ने लंबे समय से यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने और विदेशी उलझनों से बचने को अपने दूसरे कार्यकाल के एजेंडे के रूप में प्रस्तुत किया है। लेकिन फर्ग्यूसन चेतावनी देते हैं कि यदि अमेरिका अपने कर्ज संकट का समाधान नहीं करता, तो केवल ये रणनीतिक बदलाव पतन को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। वे सुझाव देते हैं कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र का भविष्य दांव पर है।

ट्रम्प के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रिपब्लिकन पार्टी के भीतर भी, आदेश पर राय जाति, जातीयता और आयु के आधार पर भिन्न हैं। श्वेत रिपब्लिकन सबसे अधिक समर्थन दिखाते हैं, जिनमें 77 प्रतिशत इसका समर्थन करते हैं। एशियाई रिपब्लिक के बीच यह समर्थन 63 प्रतिशत है।

कम से कम आठ मुकदमे पूरे देश में ट्रम्प के निर्देश को चुनौती देने के लिए अदालतों में दायर किए गए हैं। उनका कार्यकारी आदेश इमिग्रेशन को कठोर करने का प्रयास है, जो

इम्मिग्रेशन को कड़ा करने के प्रयास के रूप में आया था, जैसा कि उन्होंने अपने चुनाव अभियान में वादा किया था। यह आदेश उन बच्चों को अमेरिकी नागरिकता से वंचित करता है जो देश में अवैध रूप से या अस्थायी रूप से वीज़ा पर आई माताओं से पैदा हुए हैं और जिनके पिता न तो, अमेरिकन नागरिक हैं और न ही कानूनी निवासी हैं।

संघीय न्यायाधीशों द्वारा ट्रम्प प्रशासन के खिलाफ दिए गए निर्णय 1898 के सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय, संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम वोंग किम आर्क पर आधारित हैं, जिसमें अदालत ने चीनी आप्रवासियों से जन्मे व्यक्ति को संविधान के तहत नागरिकता प्राप्त बताया था।

तेलंगाना : सुरंग की छत गिरने से 8 मजदूर फंसे

हैदराबाद/दिल्ली, 22 फरवरी। तेलंगाना के सिंचाई मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी ने शनिवार को कहा कि श्रीशैलम सुरंग नहर परियोजना के निर्माणाधीन खंड की छत का एक हिस्सा ढ ह जाने से आठ व्यक्ति अंदर फंस गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा उन्हें बचाने के लिए सभी प्रयास किये जा रहे हैं। वहीं, एक अधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को फोन किया और सुरंग में फंसे कर्मियों को सुरक्षित निकालने पर चर्चा की। उन्होंने बचाव प्रयासों में हरसंभव मदद का आश्वासन दिया। जिस टनल में यह हादसा हुआ है, उसकी कुल लंबाई 44 किलोमीटर की है। जहां पर हादसा हुआ है, उस स्थान की हैदराबाद से कुल दूरी 120 किमी की है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भारतीय सेना की इंजीनियर टॉस्क फोर्स को मोबालाइज किया गया है।

- भारतीय सेना की इंजीनियर टास्क फोर्स भी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद कर रही है।

नागरकुरनूल जिले में दुर्घटना स्थल पर पत्रकारों से बात करते हुए सिंचाई मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विशेषज्ञों की मदद ले रही है, जिनमें पिछले साल उत्तराखंड में हुई एक घटना (सिलक्यारा सुरंग हादसे) में फंसे श्रमिकों को बचाने वाले विशेषज्ञ भी शामिल हैं। उन्होंने भारतीय सेना और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) से भी मदद मांगी है। सुरंग में फंसे लोगों में दो इंजीनियर, दो मशीन ऑपरेटर और चार श्रमिक शामिल हैं।

उत्तराखंड के...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)3

जीत के बाद त्रिवेन्द्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद तीरथ सिंह रावत और पुष्कर सिंह धामी राज्य के मुख्यमंत्री बने।

2009 के सी.ए.एम.पी.ए. दिशा निर्देशों के अनुसार, धन प्राप्त होने के बाद राज्य को उसी वर्ष या दो कृषि सत्रों के भीतर वनरोपण कार्य पूरा करना चाहिए था। रिकॉर्ड की जाँच में सामने आया कि 37 मामलों में वित्तीय मंजूरी प्राप्त करने के आठ साल से अधिक समय के बाद क्षतिपूर्ति वनरोपण कार्य शुरु किया गया। रिपोर्ट के अनुसार, इसके परिणामस्वरूप लागत में 11.54 करोड़ रूपये की वृद्धि हुई। सी.ए.जी. को, एनुअल प्लैन ऑफ ऑपरेशन्स में, नीचे से ऊपर की विफल योजना तथा अनियमित वस्तुएं शामिल करने के लिए मनमाना दृष्टिकोण अपनाए जाने के उदाहरण मिले। सी.ए.जी. ने सिफारिश की है कि राज्य प्राधिकरण को नियंत्रण रखना चाहिए और मजबूत वित्तीय प्रबंधन के लिए उचित बजटीय नियंत्रण स्थापित करना चाहिए, ताकि फंड के दुरुपयोग या डायवर्ज़न को रोका जा सके।

"एडहॉकिज़्म" कार्यवाहक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उल्लेखनीय है कि सूची जारी होने के बाद इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन (आई.एम.ए.) की ओर से राज्यपाल को चिट्ठियां लिखी गईं कि आर.यू.एच.एस. जैसी प्रतिष्ठित संस्थान में केवल राजस्थान के ही एक मैडिकल एजुकेशन प्रोफेशनल को ही कुलपति के पद पर नियुक्त किया जाए।

संभवतः आई.एम.ए. ने राज्यपाल को डॉ. प्रमोद गोविन्द राव येवले के मुद्दे पर पत्र लिखा था, क्योंकि डॉक्टर येवले प्रशिक्षित डॉक्टर नहीं। जहां तक सर्च समिति की सूची में स्थानीय डॉक्टरों का सवाल है तो आठ डॉक्टरों की सूची में से चार डॉक्टर राजस्थान से हैं। इनमें जे.एल.एन. मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर वी.बी. सिंह, एस.एम.एस. के पूर्व प्रिंसिपल व अधीक्षक और आर.यू.एच.एस. के प्रिंसिपल रह चुके डॉक्टर राजेश शर्मा, एस.एम.एस. के एडिशनल प्रिंसिपल डॉक्टर एस.एम. शर्मा और आर.एन.टी. मेडिकल कॉलेज उदयपुर के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर लाखन ओसवाल शामिल हैं। अत्यन्त ही हैरान करने वाली बात है कि उपयुक्त डॉक्टरों की कमी न, होने के बावजूद राज्य सरकार आर.यू.एच. एस. का संचाल एक अयोग्य और कार्यवाहक वी. सी. से करवाने पर उतारू है, और नई नियुक्ति नहीं कर रही है। इस संदर्भ में राज्यपाल की ओर से भी तीखी टिप्पणी करते हुए शिक्षा विभाग को पत्र लिखा गया था। इस पत्र में राज्यपाल द्वारा गंभीर आरोप भी लगाए गए थे कि (1) आर.यू.एच.एस. के अस्थाई वी. सी. ने उनके निर्देश की अवमानना करते हुए चयन समिति में विश्वविद्यालय के बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित सदस्यों की सूचना नहीं भिजवाई है, (2) विश्वविद्यालय के बोर्ड द्वारा नाम निर्देशित सदस्यों के सम्बन्ध में निर्धारित समय अवधि में कार्यवाही नहीं की गई, (3) आर.यू.एच.एस. के कार्यवाहक वी. सी. द्वारा राज्यपाल के पत्र, जिसमें स्थाई कुलपति की नियुक्ति की जानकारी मांगी गई थी, उसे भी तीन दिवस के निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं किया गया था।

राज्यपाल द्वारा इतने गंभीर आरोप लगाए जाने के बावजूद डॉक्टर धनन्जय अग्रवाल को उनके अस्थाई पद से हटाकर एक स्थाई कुलपति की नियुक्ति नहीं किया जाना, ऐसा दर्शाता है कि डॉक्टर अग्रवाल को राज्य सरकार के किसी अत्यन्त ही प्रभावशाली व शक्तिशाली व्यक्ति का समर्थन प्राप्त है।

यह तथ्य इसलिए भी चौंकाने वाला है, क्योंकि आर.यू.एच.एस. मुख्यमंत्री भजन लाल के निर्वाचन क्षेत्र में ही आता है, और मुख्यमंत्री की घोषणाओं के अनुसार, आर.यू.एच.एस. को 'एम्स' की तर्ज पर विकसित किया जाना है, परन्तु, एक अस्थाई वी. सी. के रहते हुए प्रभावशाली निर्णय कैसे लिये जा सकेंगे, क्योंकि न तो वर्तमान अस्थाई वी. सी. के पास ऐसा कार्यभार संभालने का अनुभव है और न ही पद के लिए आवश्यक योग्यता ,और अगर अदालत में इनकी नियुक्ति को चुनौती दी गई तो किसी भी दिन वर्तमान अस्थाई वी. सी. को हटाया भी जा सकता है।

शिक्षा सचिव, ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उपार्जित अवकाश का लाभ भी प्रभावित हो रहा है। इसे हाईकोर्ट में चुनौती देने पर खंडपीठ ने अक्टूबर 2023 में राज्य सरकार व संबंधित विभागों को निर्देश दिया था कि याचिकाकर्ताओं को भी एक वेतन वृद्धि सहित अन्य सेवा परिलाभ दिए जाए। इस पर याचिकाकर्ताओं को तय समय पर सेवा परिलाभ नहीं दिए गए। इसे अवमानना याचिका में चुनौती देते हुए कहा गया कि याचिकाकर्ता 30 जून 2019 को रिटायर हुए थे। ऐसे में उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ ही सेवा परिलाभ भी तभी से मिलने चाहिए थे। राज्य सरकार ने उन्हें एक जुलाई को दी जाने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दे दिया, लेकिन अंतिम वेतन वृद्धि के अन्य लाभ नहीं दिए हैं। इसलिए पूर्व में दिए अदालती आदेश की पालना कराई जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

सलेक्टिव मीडिया, कोटा के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी रोड, कोटा से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा आर.एन.आई. नं. 28446/75, **जयपुर कार्यालयः** सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोनः 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, **बीकानेर कार्यालय :** कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोनः 2200660, फैक्स 0151-2527371, **उदयपुर कार्यालयः** आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोनः 2413092, फैक्स : 0294-2410146, **अजमेर कार्यालयः** राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोनः 2627612, फैक्स:0145-2624665 **जालोर कार्यालय :-** जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्सः 02973-226424 **हिण्डौनसिटी कार्यालय :-** जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोनः 230200, 230400, फैक्सः 07469-230600 **चूरू कार्यालय :** एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्सः 01562-256908